and State sectors pertaining to tobacco growers and cultivation in the country such as production, marketing, quality, price, export market, seed requirements etc. and recommend measures to increase production and profit from the crop to the growers. It facilities coordination between research and development programmes relating ot tobacco and advice Government for improvement of quality and productivity of tobacco and other related matters as may be necessary from time to time. The Council is managed by the Ministry of Agriculture, Govt. of India.

(b) Central Tobacco Research Institute has a management committee which meets once in a year. Its latest meeting was hold on 2-7-92. Indian Tobacco Development Council does not have a management committee. However, its members meet periodically. They last met on 11-1-89 at Hyderabad.

(c) At present, Central Tobacco Research Institute has 592 staff members. Its plan expenditure during 1989-90, 1990-91 and 1991-92 was Rs. 49.91 lakhs, Rs. 15.98 lakhs and Rs. 94.49 lakhs respectively. The non-plan expenditure during these three years was Rs. 248.78 lakhs, Rs. 278.95 lakhs and Rs. 285.90 lakhs respectively.

Tobacco Development Council is provided with secretarial assistance by the Directorate of Tobacco Development, whenever it is necessary. No separate budgetary allocation is made either under plan or non-plan for Council by the government. A sum of Rs. 11,177 was spent on account of travelling allowance and daily allowance during 1989 meeting.

हिमाचल प्रदेश को मल निकासी योजनाओं के लिए अनुदान

159. **श्री महेश्वर सिंह** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1992-93 के दौरान किन-किन नगरों में मल निकासी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुदान की मांग की है;

(ख) इन योजनाओं की अनुमानित लागत क्या है; और

(ग) 1992-93 के दौरान कितनी धनराशि प्रदान की गई है और कौन-कौन सी योजनाएं सरकार के विचाराधीन हैं?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) :(क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेश सरकार ने 6 शहरों अर्थात् शिमला, मनाली, मंडी, धर्मशाला, चम्बा और सोलन के एकीकृत विकास हेतु बाह्य सहायता के लिये मल जल निर्यास घटक के लिये 42.30 करोड़ रु. सहित 102.40 करोड़ रु. अनुमानित लागत का एक परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया था । मल जल निर्यास के लिए कोई केन्द्रीय सहायता नहीं दी जाती ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

विद्यालयों में बड़ी संख्या में अधर में ही पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों के बारे में चिन्ता

*160. **श्रीमती सुषमा स्वराज** :
श्री राम जेठमलानी :

क्या **मानव संसाधन** विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 जून, 1992 के इकोनामिक टाइम्स में ?"हाई ड्राप आउट रेट ब्लेम्ड फार लिटरेसी" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व बैंक की एक अध्ययन रिपोर्ट में हमारे देश में प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों के स्तर पर पढ़ाई को अधर में ही छोड़ने वाले विद्यार्थियों की बड़ी संख्या पर गंभीर चिन्ता व्यक्त की गयी है;